सौगाते मोदी

बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं

करीब बीस करोड़ लोगों में से 32 लाख मुस्लिमों को ईद के मौके पर विशेष सौगात देने जा रहे हैं हमारे साहब, बड़े साहब हैं कब क्या बोलेंगे और क्या करेंगे...बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ ...कोई ठिकाना नहीं सरकार के मूड का कब गाली दें और कब सौगात दे दें.. बड़े बड़े राजे महाराजे ऐसे ही मूडी हुआ करते थे....सौगात उसी बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को दी जा रही है जिनके लिए पूरी बीजेपी लॉबी सिर्फ नफरती जुमले और बयान ही देती आ रही है तो अचानक ये सौगात क्यों ?हैरानी तो स्वाभाविक है।

क्या सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया अरब के शेखों से मिलने के बाद, मस्जिदों में जाने के बाद ? क्या ट्रंप की बेरुखी ने सरकार को मुस्लिम देशों को तवज्जो देने पर मजबूर कर दिया ? क्या ये सौगात महज कूटनीति के तहत है कि मुस्लिम देश में सरकार अपनी इमेज बनाने की ओर अग्रसर हो गए?

सवाल अनगिनत हैं ..जवाब सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। सवाल ये भी है कि ये सौगात मुस्लिमों के दरवाजे पर कौन ले जाए, क्या परवेश वर्मा, गिरिराज किशोर ,देवेंद्र फडणवीस , योगी जी , रमेश बिदुडी, जैसे अनेक नेता जो खुले मंच से मुस्लिमों से नफरत परोसते रहे हैं या खुद सरकार जो मुस्लिमों को कपड़ों से ही पहचानने की सीख देते हैं ?या अमित शाह जी जो शाहीन बाग को करंट लगा के खत्म करना चाहते थे.... अजीब सा लगता है सुन कर ईद के लिए, कुर्ता पजामा सेवइयां शिरखुरमा बाटा जाएगा उनके द्वारा जो मुस्लिमों को गाली दे कर ही बड़े नेता बने हैं , कैसे और किस मुंह से ये बड़े नेता जा सकेंगे मुस्लिमों के बीच जो सिर्फ गालीबाजी करते रहे हैं बरसों से !

मुस्लिमों की पढ़ाई का बजट घटा दिया गया , हज सब्सिडी न सिर्फ खत्म की बल्कि एयरलाइनों को खुली छूट भी दी हाजियों को लूटने की मौलाना आजाद स्कालरशिप खत्म , छोटी मोटी बात पर मुस्लिम होने मात्र के लिए घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं... ऐसे में सरकार की ये सौगात क्यों? मेरा तो भेजा ही काम नहीं कर रहा साहब आप कुछ समझ सके हों तो मुझे भी समझाओ।

मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि अगर ये सौगात राहुल गांधी या प्रियंका गांधी घोषित करती तो ? मीडिया नंगा नाच रहा होता क्या क्या हेडलाइन बनी होती ... जरा कल्पना कीजिए राहुल गांधी को मुल्ला गांधी घोषित कर दिया होता जैसे मुलायम सिंह यादव को मुल्ला यादव कहा जाने लगा था, किसी शेख के साथ मस्जिद में तस्वीर आती तो मीडिया नाच रहा होता, राहुल के धर्म परिवर्तन के सबूत तलाशे जा रहे होते ....

खैर हो सकता है साहब ने पिछले कुछ चुनाव का विश्लेषण किया हो कि कई सीट मुस्लिमों के समर्थन के कारण उनकी झोली में आ गई, हो सकता है साहब को अहसास हो गया हो कि मुस्लिमों को साथ लेना पड़ेगा राज करना है तो... कारण जो भी हो ...कदम अच्छा है इस से बीजेपी की मुस्लिम विरोधी छवि सुधरेगी कुछ मुस्लिम वोटर जुड़ेंगे सरकार से , खुसरो वाले प्रोग्राम में भी सरकार का भाषण मुस्लिमों को साधने वाला था और अब ये सौगात भी ...बस एक हार्दिक इच्छा यही है कि ये सारी सौगात उन लोगों तक भी पहुंचे जो घटिया राजनीति के शिकार हो कर मुस्लिम होने की सजा भुगत रहे हैं...सरकार उनको जरूरत है आपकी सौगात की कोई जेल में है और इसलिए जमानत नहीं पा रहा कि मुस्लिम है , किसी का घर महज मुस्लिम होने से जमीदोज हो गया , किसी की नौकरी जा रही मुस्लिम होने से कोई अपने फल और सब्जी के ठेले पर अपना नाम लिख के धंधा गवा बैठा इन सब को आपकी सौगात की दरकार है सरकार ....

सौगात दीजिए समानता के हक की...सौगात दीजिए सर्व धर्म सम भाव की ....सौगात दीजिए इंसाफ की....सौगात दीजिए सौहाद्र की...सौगात दीजिए नौकरियों की एकता की साथ जीने की प्यार से सम्मान से इस सौगात की जरूरत है सभी को सरकार ईद मनाने के लिए तो मुस्लिम समाज किसी की मदद नहीं चाहता उसका अपना जकात का सिस्टम ही सबकी ईद मनवा देता है , हर मुस्लिम सिवैया खा लेता है कुर्ता पजामा पहन लेता है । सौगात देनी है तो मुहब्बत की सौगात दो सरकार हम तहे दिल से आपकी मुहब्बत की सौगात कुबूल करेंगे ।

आपका हनीफ इंदौरी

देपालपुर में अवैध शराब का अड्डा बना रंगवासा

शराब तस्करी चरम पर, प्रशासन बना मूकदर्शक

देपालपुर। देपालपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब का धंधा बेलगाम हो चुका है। प्रशासन की निष्क्रियता और ठेकेदारों की खुली छूट के कारण शराब तस्करों का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि अब यह कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। सबसे अधिक शराब की अवैध आपूर्ति रंगवासा, दौलताबाद, सगडोद और चांदेर शराब दुकानों से हो रही है।

ठेकेदारों की गाड़ियां दिन-रात शराब की तस्करी में लगी हुई हैं, लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस आंख मूंदे बैठी है। रंगवासा, दौलताबाद, सगडोद और चांदेर के शराब ठेकों का प्रबंधन अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ठेके के शराब को तस्करों को आधे दाम में बेचा जा रहा है, जो इसे महंगे दाम पर ब्लैक मार्केट में खपा रहे हैं। आम लोगों तक यह शराब अवैध रूप से पहुंच रही है, लेकिन इस पूरे खेल में प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरह से नदारद है। मिलीभगत के कारण ठेकों में हर दिन लाखों की अवैध बिक्री हो रही है, और सरकार को भारी राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा है।

देपालपुर आबकारी उपनिरीक्षक की लापरवाही और निष्क्रियता इस पूरे खेल को परवान चढ़ा रही है। उनके कार्यकाल में अवैध शराब का यह धंधा बेलगाम हो गया है। उनकी मिलीभगत के कारण न सिर्फ ठेकेदारों की मनमानी चल रही है, बल्कि शराब तस्करों को भी खुली छूट मिल गई है। ठेकेदारों के निर्देश पर 'डायरी वालों' को स्टॉक भरने के लिए कहा जा रहा है ताकि समय आने पर अवैध शराब की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सके। 1 अप्रैल से नए टेंडर के क्रियान्वयन के तहत चांदेर और सगडोद ने मिलकर नया ग्रुप बनाया है, जिसमें अशोक राय ने ठेका लिया है।

उधर, रंगवासा और दौलताबाद का टेंडर अगले कुछ दिनों में होने वाला है, जहां बसंत जायसवाल के ठेका लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन ठेकेदार बदले या न बदले, अवैध शराब की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आ रही है।

देपालपुर ग्रुप के ठेकेदार विशाल पारेता को इस गड़बड़झाले में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने ठेका छोड़ दिया। अब उनके पार्टनर मुकेश चौकसे ने नया ठेका लिया है। उधर, गौतमपुरा का ठेका भी बदल गया है और अब इसे उज्जैन के व्यवसायियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। आगरा, बेटमा, घाटाबिल्लौद, कलारिया और मायल ग्रुप के ठेके रिपीट हुए हैं, जिससे इन इलाकों में भी अवैध शराब का धंधा जस का तस बना हुआ है।

देपालपुर और आसपास के इलाकों में अवैध शराब की बाढ़ आ गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आबकारी विभाग और पुलिस की इस लापरवाही का फायदा उठाकर ठेकेदारों और तस्करों ने अपने नेटवर्क को और मजबूत कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस गोरखधंधे पर कोई कार्रवाई करेगा, या फिर यह खेल इसी तरह चलता रहेगा?

सुमित्रा महाजन के पोते से मारपीट के आरोपी ने पुलिस के रवैए के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई याचिका, कोर्ट ने सरकार, डीजीपी व कमिश्नर से मांगा जवाब

इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस संजीव एस कालगांवकर की एकल पीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, इंदौर पुलिस आयुक्त सहित अन्य को आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जुलूस निकालने के मामले में नोटिस जारी कर चार हपते में जवाब मांगा है।

मामला पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व सांसद सुमित्रा महाजन के पोते से मारपीट का है जिसमें आरोपी बनाए गए सौरभ करोसिया ने पुलिस द्वारा जुलूस निकालने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं। ज्ञात हो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व सांसद सुमित्रा महाजन के पोते से उनके बेटे के कार के शो रूम में कार सर्विसिंग के विवाद में मारपीट और शो रूम में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने सौरभ करोसिया सहित अन्य लोगों को आरोपी बना सौरभ का गिरफ्तारी के बाद उसके निवास क्षेत्र में जुलूस निकाला था।

मामले में सौरभ करोसिया और अन्य आरोपियों को निचली अदालत से ही जमानत मिल गई थी। अब सौरभ करोसिया ने उसके खिलाफ दर्ज केस और पुलिस की कार्रवाई एवं रवैये को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसे स्वीकार करते न्यायालय ने आजादनगर पुलिस से केस डायरी तलब करते नोटिस जारी किए हैं।

याचिका में याचिकाकर्ता सौरभ करोसिया ने डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के साथ डीसीपी जोन-1, तत्कालीन आजादनगर एसीपी, तत्कालीन आजादनगर टीआई, पुलिस के दो व होमगार्ड जवान सहित भूषण दीक्षित व सिद्धांत को पार्टी बनाया है।

इंदौर मंडी में किसानों की फ़सल का पैसा 8 से 10 दिन में मिल रहा है किसानों को भुगतान

इंदौर। चोइथराम मंडी में किसानों को अपनी उपज लहसुन के पैसों के लिए 8 से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है और अपनी फसल के पैसों के लिए सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत करना पड़ रही है।

मंडी सचिव किसानों के भुगतान को लेकर या उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं दिखते मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार होने के साथ ही किसान नेता बबलू जाधव शैलेंद्र पटेल चंदन सिंह बड़वाया आदि ने बताया कि पूर्व में इंदौर की मंडियों की अव्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों ने मोर्चा खोला था परंतु मंडी सचिव द्वारा फर्जी Fir दर्ज करा कर हम लोगों को दबाने का डराने का प्रयास किया गया था।

हम मंडी में किसानो की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाते रहेंगे उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड के एमडी के स्पष्ट निर्देश हैं की 2 लाख तक का भुगतान किसान को उसी दिन व्यापारी से नगद भुगतान कराया जाए परंतु इस निर्देश पर इंदौर मंडी सचिव नरेश परमार अपने अधीनस्थ आने वाली मंडीयों में1 लाख रुपए से नीचे का भी भुगतान नहीं करा पा रहे।

मालूम हो की इंदौर मंडी सचिव नरेश परमार की प्रति नियुक्ति दो बार बढ़ चुकी है और वे सालों से इंदौर में पदस्थ हैं एक समय से ज्यादा एक ही जगह जमे हुए हैं इन्हें तत्काल हटाना चाहिए और किसानों का जल्द से जल्द भुगतान कराया जायें।

महावीर जयंती पर जुलूस में मराठी, गुजराती, राजस्थानी मंडली नृत्य करते हुए शामिल होंगे

इंदौर । जैन श्वेतांबर महा संघ न्यास इंदौर के कार्यालय पर महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की बैठक कर तैयारियों की चर्चा की गई |समाज के कई संगठन सोशल ग्रुप व दोनों फेडरेशन के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए |महा संघ न्यास के अध्यक्ष विजय मेहता व सचिव सुधीर सेठिया ने बताया की शहर के कई इलाको में 6 अप्रैल को बस्ती के लोगों को भोजन प्रसादी बाटी जाएगी। जुलूस के अलावा रैली निकाली जाएगी। पंजाबी ढोल, भजन मंडली व कई प्रकार की झाँकियाँ मराठी मंडली नृत्य करते हुए चलेगी |शहर के साधु संत पूरे समय जुलूस की शोभा बढ़ाएँगे। खतरगच्छ श्री संघ के, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय छाजेड़ ने भी अपनी बात कही |108 युवा इंद्र बन कर भगवान महावीर का रथ खीचेंगे। कैलाश नाहर, यशवंत जैन, शिखर चंद बाफना, रितेश कटकनी, विमल नाहर, मनोहर लोढ़ा, सुधीर सेठिया, हेमंत गुगलिया, नरेंद्र भटेवरा, नरेंद्र संचेती, नरेंद्र भंडारी, रुचिल दोशी, नीलेश पोखरना, कीर्ति शाह, योगेन्द्र सांड ने बताया की जुलूस 10 अप्रैल को सुबह 8 बजे रजवाड़ा से शुरू होकर खजूरी बाज़ार,गोरा कुंड,मल्हार गंज,बड़ा गणपति,महावीर बाग से होता हुआ दलाल बाग पहुँचेगा। धर्म सभा एवं स्वामिवात्सल्य होगा। राजकुमार सुराणा,दिनेश हुँडिया, शांतु पालरेचा, पुखराज पामेचा ने बताया की दिनांक 10 अप्रैल को अपना व्यवसाय बंद कर परिवार सहित जुलूस में शामिल होंगे ।

एक्यूआई से ऊपर है, वहां की हवा में सांस लेना दिन में 25-30 सिगरेट पीने के बराबर

इंदौर। श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रभावी उपचार समाधानों के प्रचार-प्रसार की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता में, सिप्ला लिमिटेड की मरीज समर्थन पहल, ब्रीदफ्री, देशभर में अपनी प्रभावशाली यात्रा को ब्रीदफ्री यात्रा के साथ जारी रखे हुए है।

यह यात्रा लोगों को उनके श्वसन स्वास्थ्य का आकलन करने और समझने में मदद करने के लिए व्यापक जागरूकता और सीधे मरीज की सहायता को समर्पित है। अस्थमा और सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) जैसे पुराने श्वसन रोगों के लिए स्क्रीनिंग 'चैनलों' तक पहुंच बेहतर करने के लक्ष्य के साथ, ब्रीदफ्री यात्रा ने 335 से अधिक शहरों (नगरों) में यात्रा की है, 6,600 से ज्यादा शिविर आयोजित किए हैं और देश भर में करीब 10 लाख मरीजों की सहायता की है।

बढ़ती चुनौतियों के बीच श्वसन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, डॉ. सूरज वर्मा, छाती रोग विशेषज्ञ, इंदौर, ने कहा, लाखों लोग रोजाना वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण के कारण उड़ने वाली धूल और कृषि कचरे को जलाने से उत्पन्न होने वाले हानिकारक कणों (पीएम 2.5 और पीएम10) के खतरनाक स्तर के संपर्क में आते हैं।

इसके अलावा, जिन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 500 से ऊपर है, वहां की हवा में सांस लेना दिन में 25-30 सिगरेट पीने के बराबर है। ये जागरूकता और कार्रवाई के बीच अंतर को खत्म करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, डॉक्टर ने कहा, अस्थमा और सीओपीडी का प्रभावी प्रबंधन बीमारी का जल्दी पता चलने और डॉक्टर के बताये उपचारों का सख्ती से अनुपालन करने से होता है। हालांकि, इनहेलेशन थेरेपी से संबंधित बदनामी या चर्चा तथा गलतफहमियों के कारण और रोजाना के लक्षणों की बजाय गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर इन स्थितियों का नियंत्रण खराब रहता है।

सरकार का एक और गलत कदम

विगत दिनों संसद में पारित वित्त बिल में आठवें पे कमीशन पर जो अनुशंसा की जाकर इस बिल को पारित किया गया है,वह एक तरह से संसद द्वारा अपने पूर्व अधिकारियों की पेंशन पर सीधा सीधा कुठाराघात तो है ही, यह ठीक वैसा है जैसे संतानों द्वारा पैतृकों को जीवन अधिकार से वंचित करना, महंगाई के युग में पेंशन न बढ़ना मतलब पूर्व अधिकारियों को उनके सामान्य जीवन यापन के अधिकार से न केवल वंचित किया जा रहा है वरन उनके द्वारा अपने अधिकारों के लिए कानूनी रूप से लड़ने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है ताकि वे न्यायालय में इसे न तो चुनौती दे सकेंगे और न ही न्यायालय इस बारे में अपने निर्णय से शासन को सेवा निवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को राहत प्रदान कर पाएंगे।

अतार्किक, अमानवीय और सेवा निवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ घोर दमनात्मक निर्णय शासन ने ले लिया है।यह एक तरह से रिटायर सेवकों को दिया गया दमनात्मक तोहफा है जिसे शासन ने सेवा के बदले देकर पुरस्कृत किया है।

मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाले शासन के राज में खर्चे कम करने का यह एक सरल उपाय है जिसके द्वारा सांसदों को बढ़े हुए भत्तों का भुगतान आसानी से किया जा सकेगा या मुफ्त रेवड़ी बांटने में सुविधा होगी।

अरूण कुमार जैन

पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला मारने वाले पति को उम्र कैद

इन्दौर। अपर सत्र न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव की कोर्ट ने पारिवारिक विवाद में ही अपनी पत्नी ममताबाई को केरोसिन डालकर जिंदा जला कर मारने वाले उसके आरोपी पति अनिल दानल को उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 11 जून 2021 को दोपहर करीब 12 बजे अनिल दानल निवासी डायमंड पैलेस कालोनी कनाड़िया और उसकी पत्नी ममताबाई का काम पर जाने की बात को लेकर हुए विवाद में अनिल ने पत्नी ममता पर केरोसिन उंडेलकर आग लगा दी जिससे वह बुरी तरह जल गई उसे गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान 15 जून को उसकी मौत हो गई। ममताबाई घरों में साफ-सफाई का काम करती थी। अभियोजन पैरवी कर रहे एजीपी उमेश यादव के अनुसार मृतका ममता बाई ने अपने मृत्युपूर्व कथन में पति द्वारा जलाने की पुष्टि की थी जो भी अहम साक्ष्य था वहीं प्रकरण में 18 गवाहों के बयान कराए गए। जिसके बाद कोर्ट ने अनिल को सजा सुनाई।

कार्टून कोना..........

बंद होगा फर्जीवाड़ा...लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदक को ही देना होगा टेस्ट

इंदौर। प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस की व्यवस्था ऑनलाइन किए जाने के बाद से आवेदकों के बजाए एजेंट ही टेस्ट देकर लाइसेंस बनाने का काम कर रहे हैं। इसे देखते हुए अब परिवहन विभाग व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अब लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के दौरान आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग बायोमैट्रिक या वेबकेम की व्यवस्था को अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है।

जल्द प्रदेश में लाइसेंस टेस्ट के समय आवेदक की उपस्थिति चेक करने के लिए बायोमैट्रिक या वेबकेम को अनिवार्य करने की तैयारी

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करीब ढाई साल पहले केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा लाइसेंस की व्यवस्था को सेंट्रल सर्वर 'सारथी' से जोड़ा गया था। इसके तहत आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आरटीओ आने की अनिवार्यता को खत्म करने के साथ ही ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था शुरू की गई थी।

इस व्यवस्था की शुरुआत से ही आवेदकों के स्थान पर एजेंट और एमपी ऑनलाइन संचालक पैसे लेकर खुद टेस्ट देकर आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस बनाकर दे देते हैं। आवेदकों को सिर्फ अपने आधार से लिंक मोबाइल पर आए ओटीपी को उनसे शेयर करना होता है। शुरुआत से ही इस व्यवस्था को लेकर फर्जीवाड़े की बातें सामने आ रही हैं।

इसे देखते हुए परिवहन विभाग अब यह सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहा है कि आवेदक ही टेस्ट दे, न कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति। आरटीओ के अधिकारियों ने बताया कि इसे लेकर मुख्यालय स्तर पर सारथी पोर्टल पर अपडेशन की तैयारी की जा रही है।

इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि टेस्ट के समय आवेदक मौजूद है इस बात को चेक किया जाएगा।

इसके लिए या तो टेस्ट के वक्त उसके बायोमैट्रिक लिए जाएंगे या वेबकेम को शुरू किया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि आवेदक द्वारा ही टेस्ट दिया जा रहा है।

बायोमैट्रिक शुरू होने पर घर बैठे नहीं बन पाएंगे लाइसेंस

विशेषज्ञों के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा की जा रही यह व्यवस्था अच्छी है और इसे जल्द लागू किए जाने की जरूरत है। हालांकि अगर इस व्यवस्था में बायोमैट्रिक टेस्ट जैस फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतलियों से जांच को सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था की जाती है तो विभाग द्वारा घर बैठे लर्निंग लाइसेंस जारी किए जाने की बातें जारी नहीं रह पाएंगी, क्योंकि इन टेस्ट के लिए जरूरी उपकरण सिर्फ एमपी ऑनलाइन सेंटर्स पर ही उपलब्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में वेबकेम की व्यवस्था ज्यादा बेहतर मानी जा रही है।